Title: Need to withdraw the decision taken by the Government regarding recruitment in Defence services on the basis of population in case of Himachal Pradesh.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी, पिछड़ा और सीमाप्रान्त प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्दर रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, उद्योग कम हैं और इस कारण यहां के नौजवान सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना अपना गौरव समझते हैं। लेकिन पिछले दिनों सरकार ने एक ऐसा निर्णय किया, जिसका दुपरिणाम हिमाचल प्रदेश पर पड़ा। सरकार ने निर्णय लिया कि देश के राज्यों की आबादी के आधार पर सेना में भर्ती की जायेगी, इसका बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश पर दुपरिणाम हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब भी विगत लड़ाइयां हमारी देश की हुईं तो उन लड़ाइयों में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कारगिल की लड़ाई में भी 52 से अधिक नौजवानों ने शहादत देकर देश के शहीदों के रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यहां के नौजवानों ने लड़ाइयों में सबसे अधिक चक्र भी प्राप्त किये हैं। देश में अब तक हिमाचल प्रदेश में चार परमवीर चक्र जवानों ने प्र ाप्त किये हैं, अशोक चक्र एक और महावीर चक्र 15 जवानों को मिले हैं, कीर्ति चक्र 14 और वीर चक्र 67 जवानों को प्राप्त हुए हैं। जो निर्णय सरकार ने किया है कि आबादी के आधार पर भर्ती की जायेगी, इसके कारण हिमाचल प्रदेश के नौजवान जो सेना के अन्दर अपना योगदान देने में गौरव समझते हैं, उनकी भावनाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए मेरा भारत सरकार के रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें ताकि वहां से अधिक मात्रा में लोग सेना में भर्ती हो सकें। धन्यवाद।